



Flal
31/10/97

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 305]
No. 305]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 1997/श्रावण 7, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 1997/SHRAVANA 7, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1997

35/97-एन टी-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 428 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8 ख की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) अधिनियम से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) "नाजुक परिस्थितियाँ" से ऐसी परिस्थितियाँ अभिप्रेत हैं जिनमें इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि ऐसी वर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन हुए आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है और अन्तर्निम सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण के बिलंब से अपूरणीय नुकसान होगा।

(ग) "वर्धित मात्रा" के अन्तर्गत घरेलू उत्पादन में चाहे आत्यंतिक रूप से या आपेक्षिक रूप से आयातों में वृद्धि भी है;

(घ) "हितवद् पक्षकार" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं —

(1) किसी ऐसी वस्तु का जो सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण के अधीन है कोई निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या उमका आयातकर्ता या किसी व्यापार या कारखाने संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता है;

(2) निर्यात करने वाले देश की सरकार; और

- (iii) भारत में ऐसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यापार या कारबार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य भारत में वैसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु का उत्पादन या व्यापार करते हैं;
- (ङ) "वैसी ही वस्तु" से ऐसी कोई वस्तु अभिप्रेत है जो सभी प्रकार से अन्वेषणाधीन वस्तु के तदरूप या समान है;
- (च) "अन्ततिम शुल्क से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क अभिप्रेत है;
- (छ) "विनिर्दिष्ट देश" से अभिप्रेत है ऐसा देश या राज्य क्षेत्र जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और उसके अंतर्गत देश या राज्यक्षेत्र है जिसके साथ भारत सरकार सार्वधिक अनुकूल राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए करार कर लिया है।
- (ज) ऐसे सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके क्रमशः दिए गए हैं।

3. महानिदेशक (सुरक्षा) की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पंक्ति के नीचे का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे वह ठीक समझे इन नियमों के प्रयोजनों के लिए महानिदेशक (सुरक्षा) जिसे इसमें इसके पश्चात् महानिदेशक कहा गया है नियुक्त कर सकते हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है जो वह ठीक समझे।

4. महानिदेशक के कर्तव्य—इन नियमों के अधीन रहते हुए महानिदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

- (1) भारत में किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के विद्यमानता का अन्वेषण करना;
- (2) सुरक्षा शुल्क के लिए दायी वस्तु की पहचान करना;
- (3) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बारे में केन्द्रीय सरकार को अन्ततिम या अन्यथा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना।
- (4) निम्नलिखित सिफारिश करना,—
 - (i) शुल्क की ऐसी रकम की सिफारिश करना जो यदि उद्ग्रहीत होती तो घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति की आशंका को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी;
 - (ii) सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण की कालावधि की सिफारिश करना और जहां इस प्रकार सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक है, वहां सकारात्मक समायोजन के सुकर बनाने के लिए यथोचित प्रगामी उदारीकरण की सिफारिश करना।
- (5) सुरक्षा शुल्क के जारी रखे जाने की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करना।

5. अन्वेषण का शुरु किया जाना—(1) उपनियम (4) में यथा उपबोधित के सिवाय, महानिदेशक ऐसी गंभीर वैसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु के घरेलू उत्पादक द्वारा या उसकी ओर से किसी लिखित आवेदन की प्राप्ति पर घरेलू उत्पादन को ऐसी वर्धित मात्रा में किसी वस्तु के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को आत्यांतिक या संबद्ध रूप से "गंभीर क्षति" कारित होने या गंभीर क्षति कारित करने की आशंका की विद्यमानता को अवधारित करने के लिए अन्वेषण शुरू करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन उस प्ररूप में होगा जो इस निमित्त महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसा आवेदन,—

- (क)—
- (i) वर्धित आयात;
 - (ii) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका;
 - (iii) आयात और अभिकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच आकस्मिक संबंध के साक्ष्य; और
- (ख) आयात प्रतियोगिता में सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए गए प्रयासों या ली जाने वाली योजनाओं या दोनों के विवरण द्वारा समर्थित होगा।
- (3) महानिदेशक उपनियम (1) के अधीन दिए गए आवेदन के अनुसरण में अन्वेषण तब तक शुरु नहीं करेगा जब तक कि वह आवेदन में दी गई साक्ष्य की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच पड़ताल नहीं कर लेता है और स्वयं यह समाधान कर लेता है कि निम्नलिखित के विषय में पर्याप्त साक्ष्य है—
- (क) वर्धित आयात;
 - (ख) गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका; और

(ग) वर्धित आयात और अभिकथित क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच आकस्मिक संबंध।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त से, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (3) के खंड (ख) और खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान रहती है।

6. अन्वेषण को शांति करने वाले सिद्धान्तः— (1) महानिदेशक भारत में किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका को अवधारित करने के लिए अन्वेषण शुरू करने के विनिश्चय के पश्चात् अपना विनिश्चय अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी अर्थात्:—

- (i) निर्यात करने वाले देशों का नाम और अन्तर्वर्तित वस्तु;
- (ii) अन्वेषण शुरू किए जाने की तारीख;
- (iii) ऐसे तथ्यों के विवरण का सारांश जिन पर गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का अभिकथन आधारित है;
- (iv) अन्वेषण के शुरू किए जाने के लिए कारण;
- (v) वह पता जिस पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन भेजे जाएं; और
- (vi) हितबद्ध पक्षकारों को उनके दृष्टिकोण की जानकारी के लिए अनुज्ञात समय सीमा।

(2) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को और अन्य सबद्ध मंत्रालयों को, ऐसी वस्तु जिसके वर्धित आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका अभिकथित की गई है के ज्ञात निर्यात कर्ताओं को निर्यात करने वाले देशों की संबद्ध सरकारों को और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की जाएगी।

(3) महानिदेशक नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति—

- (i) ज्ञात निर्यात कर्ताओं या संबद्ध व्यापार संगम,
- (ii) निर्यात करने वाले देश की सरकार, और
- (iii) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को,

परन्तु वह आवेदन की एक प्रति लिखित में अनुरोध पर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी उपलब्ध कराएगा।

(4) महानिदेशक निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और हितबद्ध देशों की सरकारों से ऐसे प्ररूप में जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी जानकारी की अपेक्षा करने वाली सूचना जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्तियों तथा सरकारों द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे पर्याप्त कारण उपदर्शित किए जाने पर महानिदेशक अनुज्ञात करे, लिखित रूप में ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उम तारीख से, जिसको ये दस्तावेज महानिदेशक द्वारा निर्यात वाले देश के समुचित राजनायिक प्रतिनिधि को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए थे या सप्रेषित किए गए थे, एक सप्ताह के पश्चात् हुए समझे जाएंगे।

(5) महानिदेशक अन्वेषणाधीन वस्तु के औद्योगिक उपभोक्ता और जहां वस्तु फुटकर स्तर पर सामान्य रूप से विक्रीत की जाती है वहां प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों का ऐसी जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगा जो अन्वेषण के लिए सुसंगत है।

(6) महानिदेशक किसी हित बद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अन्वेषण के लिए सुसंगत जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु ऐसी मौखिक जानकारी पर महानिदेशक केवल तब ही विचार करेगा जब वह लिखित रूप में तत्पश्चात् पुनः प्रस्तुत की जाती है।

(7) महानिदेशक एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे प्रस्तुत की गई साक्ष्य को अन्वेषण में भाग लेने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।

(8) उस मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार युक्त युक्त काला अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी के लिए पहुंच से इन्कार करता है, या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, यहां महानिदेशक उसको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और ऐसी परिस्थितियों में जो वह ठीक मामले केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा।

7. गोपनीय जानकारी—(1) नियम 6 के उपनियम (1), (3) और (7), नियम 9 के उपनियम (2) और नियम (11) के उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सूचना जो गोपनीय प्रवृत्ति की है या जो गोपनीय आधार पर दी गई है कारण दर्शित करने पर महानिदेशक द्वारा प्रकाश की मानी जाएगी और उसे इस प्रकार की जानकारी देने वाले पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के बिना पकट नहीं किया जाएगा।

(2) महानिदेशक गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से उसका गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बताया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार महानिदेशक को ऐसे कारणों का एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि महानिदेशक का यह सामधान हो जाता है कि गोपीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी देने वाला जानकारी को सर्वविदित करने का साधारण या संक्षिप्त रूप में उसका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की तब तक अवहेलना कर सकेगा जब तक कि समुचित स्रोतों से इसके समाधान के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाता है कि जानकारी सही है।

8. गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का अवधारण—महानिदेशक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का अवधारण, अन्य बातों के साथ इन नियमों के उपाबंध में अधिकथित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगा।

9. प्रारंभिक निष्कर्ष—(1) महानिदेशक अन्वेषण के संचालन के साथ उसकी कार्यवाही को शीघ्रता से अग्रसर करेगा और नाजुक परिस्थितियों में गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के विषय में वह प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(2) महानिदेशक उसकी प्रारंभिक निष्कर्ष के विषय में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(3) महानिदेशक सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजेगा।

10. अंतिम शुल्क उद्ग्रहण—केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 8ख. की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार महानिदेशक की प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर अनन्तिम शुल्क अधिरोपित कर सकेगी।

परन्तु ऐसा शुल्क उस तारीख से, जिसको यह अधिरोपित किया गया या केवल दो सौ दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

11. अंतिम निष्कर्ष—(1) महानिदेशक अन्वेषण शुरू करने की तारीख से 8 मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे,

(i) घरेलू उद्योग को अन्वेषण के अधीन वस्तु के वर्धित आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है; और

(ii) वर्धित आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच आकस्मिक संबंध का अवधारण करेगा।

(2) महानिदेशक शुल्क की ऐसी रकम जो यदि उद्ग्रहीत होगी तो गंभीर क्षति को रोकने या उसके उपाय के लिए और सकारात्मक समायोजन को शुरू बनाने के लिए पर्याप्त होगी के विषय में भी अपनी सिफारिश देगा।

(3) महानिदेशक शुल्क के उद्ग्रहण के लिए कालावधि के विषय में भी अपनी सिफारिश देगा।

परन्तु जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक है वहां महानिदेशक सकारात्मक समायोजन को शुरू बनाने के लिए पर्याप्त प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेगा।

(4) यदि अन्तिम निष्कर्ष सकारात्मक है तो उसमें तथ्यों और विधि के मामले पर सभी सूचना तथा वे कारण जिनसे निर्णय प्रेरित हुआ है अंतर्निहित होंगे।

(5) महानिदेशक अंतिम निष्कर्ष के विषय में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्ष के विषय में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजेगा।

12. शुल्क का उद्ग्रहण—(1) केन्द्रीय सरकार अंतिम निष्कर्ष के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद को भारत में आयातकरण पर ऐसी रकम से अतिरिक्त जो गंभीर क्षति को रोकने या उसके उपाय के लिए और सकारात्मक समायोजन को शुरू बनाने के लिए पर्याप्त पाई गई है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुरक्षा शुल्क अधिरोपित कर सकेगी।

(2) यदि महानिदेशक का अंतिम निष्कर्ष सकारात्मक है जो कि उस प्रथम दृष्टया साक्ष्य के प्रतिकूल है जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो केन्द्रीय सरकार नियम 11 के अधीन महानिदेशक द्वारा अंतिम निष्कर्ष के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर अनन्तिम शुल्क को यदि कोई अधिरोपित की गई हो वापिस ले लेगी।

13. गैर विभेदकारी आधार पर शुल्क का अधिरोपण—नियम 10 या नियम 12 के अधीन अधिरोपित कोई भी सुरक्षा शुल्क गैर विभेदकारी आधार पर होगा और ऐसी वस्तु के सभी आयातों को उसके स्रोत का विचार किए बिना लागू होगी।

14. शुल्क के प्रारंभ की तारीख—(1) नियम 10 या 12 के अधीन उद्ग्रहीत सुरक्षा शुल्क ऐसा शुल्क अधिरोपित करने वाली अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनन्तिम शुल्क उद्ग्रहीत की जाती है और जहां महानिदेशक ने यह निष्कर्ष अभिलिखित कर लिया है कि वर्धित आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है वहां उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि ऐसा सुरक्षा शुल्क अनन्तिम शुल्क के उद्ग्रहण की तारीख से प्रभावी होगी।

15. **शुल्क का प्रतिदाय**—यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् अधिरोपित सुरक्षा शुल्क पहले से अधिरोपित और संग्रहीत अनंतिम शुल्क से निम्न है तो आयातकर्ता को अन्तरीय का प्रतिदाय किया जाएगा।

16. **कालावधि**—(1) नियम 12 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क केवल ऐसे समय की अवधि के लिए होगी जो गंभीर क्षति को रोकने या उपाय के लिए और सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) इस नियम के उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 12 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क जब तक कि उससे पूर्व वापस न ले लिया गया हो इसके अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका के समायोजन के लिए उपाय कर लिए हैं और यह आवश्यक है कि सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण को जारी रखा जाना चाहिए, तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार कर सकेगी:

परन्तु या और कि किसी भी दशा में सुरक्षा शुल्क का उम्र तारीख से, जिसको ऐसी शुल्क प्रथमतः अधिरोपित की गई थी, दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिए अधिरोपित किया जाना जारी नहीं रहेगा।

17. **शुल्क का उद्गारीकरण**—यदि नियम 12 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क की कालावधि एक वर्ष से अधिक है तो शुल्क उसके अधिरोपण की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर अधिकाधिक उद्गारीकृत होगी।

18. **पुनर्विलोकन**—(1) महानिदेशक सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण को जारी रखे जाने की आवश्यकता का समय समय पर पुनर्विलोकन करेगा और उसको प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(i) गंभीर क्षति को रोकने या उसके उपचार के लिए सुरक्षा/शुल्क आवश्यक है और इस बात की साक्ष्य है कि उद्योग निश्चित रूप से समायोजन कर रहा है, वह शुल्क का अधिरोपण जारी रखा जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा;

(ii) ऐसी शुल्क का अधिरोपण जारी रखा जाने के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है, उसके प्रत्याहरण के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा।

परन्तु जहां सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की अवधि तीन वर्ष से अधिक है, यहां महानिदेशक प्रत्याहरण के लिए ऐसे अधिरोपण की मध्यावधि से पूर्व स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और यदि समुचित है तो ऐसे सुरक्षा शुल्क के प्रत्याहरण के लिए या शुल्क के उद्गारीकरण के बढ़ाने के लिए सिफारिश करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन शुरू किया गया कोई भी पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलोकन के शुरू किए जाने की तारीख से आठ मास के भीतर या जैसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पूरा कर लिया जायेगा।

(3) नियम 5, 6, 7 और 11 के उपबंध पुनर्विलोकन की दशा में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

उपाबंध

(नियम 8 देखिए)

(1) अन्वेषण में यह अवधारित करने के लिए कि वर्धित आयात से किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, महा-निदेशक उस उद्योग की अवस्थिति पर उसके आचरण की प्रकृति के लिए उद्देश्य और अनुमान्य सभी सुसंगत कारकों का मूल्यांकन करेगा विशेष तथा संबद्ध वस्तु के आयात में आन्तरिक या आपेक्षिक रूप में वृद्धि की दर और रकम, वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के शेयर, विक्रय, उत्पादन, उत्पादकता, उपयोग क्षमता, लाभ और हानि तथा नियोजन के स्तर में परिवर्तन।

(2) पैरा (1) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अन्वेषण वस्तुविष्ट साक्ष्य के आधार पर संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात और गंभीर क्षति या उसकी आशंका के बीच आकस्मिक संबंधता विद्यमान होने का प्रदर्शन नहीं करता है। जब घरेलू उद्योग को उसी समय वर्धित आयात से भिन्न कारक क्षति कारित कर रहे हों तब ऐसी क्षति वर्धित आयात से होना नहीं मानी जाएगी। ऐसी दशाओं में महानिदेशक ऐसी शिकायत को प्रतिपाटन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए यथा समुचित प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा।

[फा. सं. 526/4/96-सी.शु. (टी.यु.)]

ए.एस. बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 1997

NO. 35/97-NT—CUSTOMS

G.S.R. 428 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1 Short title and commencement—(i) These rules may be called the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) "Critical circumstances" means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry;
- (c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production;
- (d) "Interested Party" includes—
 - (i) any exporter or foreign producer or the importer of an article subjected to investigation for purposes of imposition of safeguard duty or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporter or importers of such an article.
 - (ii) the government of the exporting country; and
 - (iii) a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India;
- (e) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation;
- (f) "Provisional Duty" means a safeguard duty imposed under sub-section (2) of section 8B of the Act.
- (g) "Specified Country" means a country or territory which is a member of the World Trade Organisation and includes the country or territory with which the Government of India has an agreement for giving it the most favoured nation treatment;
- (h) all words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. **Appointment of Director General (Safeguard)**—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or such other officer as it may think fit as the Director General (Safeguard) here in after referred to as the Director General for the purposes of these rules.

(2) The Central Government may provide to the Director General the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. **Duties of the Director General**—Subject to the provisions of these rules, it shall be the duty of the Director General—

- (1) to investigate the existence of "serious injury" or "threat of serious injury" to domestic industry as a consequence of increased import of an article into India;
- (2) to identify the article liable for safeguard duty;
- (3) to submit his findings, provisional or otherwise to the Central Government as to the "serious injury" or "threat of serious injury" to domestic industry consequent upon increased import of an article from the specified country
- (4) to recommend,—
 - (i) the amount of duty which if levied would be adequate to remove the injury or threat of injury to the domestic industry.
 - (ii) the duration of levy of safeguard duty and where the period so recommended is more than a year, to recommend progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.
- (5) to review the need for continuance of safeguard duty.

5. **Initiation of Investigation**—(1) Except as provided in sub-rule (4) The Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like article or directly competitive article, initiate an investigation to determine the existence of "serious injury" or "threat of serious injury" to the domestic industry, caused by the import of an article in such increased quantities, absolute or relative to domestic production.

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by:—(a) evidence of:—

- (i) increased imports;
- (ii) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;
- (iii) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury; and

(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.

(3) The Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding—

- (a) increased imports;
- (b) serious injury or threat of serious injury; and
- (c) a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1), the Director General may initiate an investigation *suo motu* if he is satisfied with the information received from any Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-rule (3).

6. Principles Governing Investigations—(1) The Director General shall, after he has decided to initiate investigation to determine the serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased import of an article into India, issue a public notice notifying his decision thereto. The public notice shall inter alia, contain adequate information on the following, namely:—

- (i) the name of the exporting countries and the article involved.
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based;
- (iv) reasons for initiation of investigation.
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed; and
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

(2) A copy of the public notice shall be forwarded by the Director General to the Central Government in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, known exporters of the article the increased import of which has been alleged to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry, the governments of the exporting countries concerned and other interested parties.

(3) The Director General shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 5 to—

- (i) the known exporters, or the concerned trade association,
- (ii) the governments of the exporting countries; and
- (iii) the Central Government in the Ministry of Commerce;

Provided that the Director General shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested party.

(4) The Director General may issue a notice calling for any information in such form as may be specified by him from the exporters, foreign producers and governments of interested countries and such information shall be furnished by such persons and governments in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Director General may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.—For the purpose of this rule the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were sent by the Director General by registered post or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country

(5) The Director General shall also provide opportunity to the industrial user of the article under investigation, and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation.

(6) The Director General may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Director General only when it is subsequently submitted in writing.

(7) The Director General shall make available the evidence presented to him by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.

(8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Director General may record his findings on the basis of the facts available to him and make such recommendations to the Central Government as he deems fit under such circumstances.

7 Confidential information—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 9 and sub-rule (5) of rule 11, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Director General and shall not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The Director General may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Director General a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, he may disregard such information unless it is demonstrated to his satisfaction from appropriate sources that such information is correct.

8 Determination of serious injury or threat of serious injury.—The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, *inter alia*, the principles laid down in Annex to these rules.

9 Preliminary findings.—(1) The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary findings regarding serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall issue a public notice regarding his preliminary findings.

(3) The Director General shall send a copy of the public notice to the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance.

10 Levy of provisional duty.—The Central Government may in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 8B of the Act, impose a provisional duty on the basis of the preliminary findings of the Director General :

Provided that such duty shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date on which it was imposed.

11 Final findings.—(1) The Director General shall, within 8 months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether,—

(a) the increased imports of the article under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and

(b) a causal link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall also give its recommendation regarding amount of duty which, if levied, would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of levy of duty.

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General shall also recommend progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.

(4) The final findings if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.

(5) The Director General shall issue a public notice recording his final findings.

(6) The Director General shall send a copy of the public notice regarding his final findings to the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance.

12. Levy of duty.—(1) The Central Government may, impose by a notification in the Official Gazette, upon importation into India of the product covered under the final finding, a safeguard duty not exceeding the amount which has been found adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.

(2) If the final finding of the Director General is negative, that is contrary to the *prima facie* evidence on whose basis the investigation was initiated, the Central Government shall within thirty days of the publication of final findings by the Director General under rule 11, withdraw the provisional duty imposed, if any.

13. **Imposition of duty on non-discriminatory basis.**—Any safeguard duty imposed under rule 10 or rule 12 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, irrespective of its source.

14. **Date of commencement of duty.**—(1) The Safeguard duty levied under rule 10 or rule 12 shall take effect from the date of publication of the notification, in the Official Gazette imposing such duty.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a provisional duty has been levied and where the Director General has recorded a finding that increased imports have caused or threaten to cause serious injury to domestic industry it shall be specified in the notification under sub-rule (1) that such safeguard duty shall take effect from the date of levy of provisional duty.

15. **Refund of duty.**—If the safeguard duty imposed after the conclusions of the investigation is lower than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

16. **Duration.**—(1) The duty levied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of this rule duty levied under rule 12 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of its imposition :

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition :

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

17. **Liberalization of duty.**—If the duration of the duty levied under rule 12 exceeds one year, the duty shall be progressively liberalized at regular intervals during the period of its imposition.

18. **Review** —(1) The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that,—

(i) safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;

(ii) there is no justification for the continued imposition of such duty, recommend to the Central Government for its withdrawal :

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the mid-term of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalisation of duty.

(2) Any review initiated under sub rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.

(3) The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall *mutatis mutandis* apply in the case of review.

ANNEXURE

(See rule 8)

In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.

1911 GI/47-2.

(2) The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the casual link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports. In such cases, the Director General may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.

[F. No. 526/4/96-CUS(TU)]

A. S. BEDI, Under Secy.